



हजार छूरों की तुलना में चार विरोधी अखबारों से अधिक डरना चाहिए।

-नेपोलियन बोनापार्ट



बारिश की भेट बढ़ा मैच, ऑस्ट्रेलिया... 7 | मणिपुर में सामाजिक व सियासी... 3 | महाकुंभ की कमाई से मृतकों के... 2

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री के बयान पर कोहराम पुणे एपकांड पर की शर्मनाक टिप्पणी

- » महायुति सरकार की पूरे देश में थू-थू
- » योगेश कदम के बयान से लग रहा है आरोपी के साथ खड़ी है सरकार!
- » गृह राज्य मंत्री ने बोला शांतिपूर्वक तरीके से हुआ रेप

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। फारस ट्रैक आदलातें, सख्त कानून और फांसी की सजा। देश में बलात्कार को रोकने के लिए वह सबकुछ किया गया जो संभव के दायरे में आता है। लेकिन न तो सूरत बदली और न ही मानसिकता। बस फर्क सिर्फ इतना आया कि दिल्ली में बालत्कार बलती बस में हुआ था और महाराष्ट्र में खड़ी बस में एक युवती के साथ बालत्कार किया गया।

यही नहीं इंसानियत को तार-तार कर देने वाले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान ने पौरे देश में तूफान मचा दिया है। कदम ने कहा है कि ऐसे शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है लड़की ने शेर क्यों नहीं मचाया। उनके इस बयान पर विवाद हमलावर है और जनता उनके बयान की भर्तस्ता कर रही है। कांग्रेस ने फडणवीस सरकार से तुरंत गृह राज्यमंत्री को बाहर करने की अपील की है।

सरकार के घटक दलों ने मांगी है फांसी की सजा

यह बात सही है कि सरकार में साथ दे रहे शिव सेना और अंजीत पवार दोनों ने ही घटना की निंदा की है और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। ऐसे में बीजेपी सरकार में मंत्री योगेश कदम ने क्या यह बयान तोट बैंक पालिटिक्स के तहत दिया है यह समझना जरूरी होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने जनता के सहयोग से रेपेस्ट को गिरफ्तार करने में सफलता पाई।

अब बया करेंगे सीएम फडणवीस

असंवेदनशील बयान पर बीजेपी चुप क्यों?

बड़ा सवाल यहीं है कि यदि इस तरह का बयान किसी गैर भाजपाई राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने दिया होता तो क्या होता? बीजेपी आज भी मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान को लेकर तरह—तरह के व्यंग कसती है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी इस बयान को यात दिलाया था तो सदन में काफी हंगामा हो गया था। ऐसे में यदि इस संवेदनशील मुद्रदे पर सरकार के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति

असंवेदनशील बयान जारी करता है तो फिर उसके क्या मायने होंगे।

नहीं बदली सूरत

दिल्ली के निर्भया रेप कांड के बाद देश में रेप को लेकर सख्त कानून बने। लोगों को लगा कि कानून बनने से और दंड मिलने से अपराधियों के मन में भय व्यस होगा और रेप होना कम होगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेप की घटनाओं में कभी नहीं आयी। दिल्ली से मिलता जुलता कांड महाराष्ट्र में हो गया। वहां खड़ी बस में युवति के साथ रेप कर दिया गया। रेप के बाद जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली में हुई थी उस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र में देखेने को नहीं मिला। बड़ा सवाल यहीं है कि आखिर गृह राज्य मंत्री को रेप को जस्टीफाई करने की क्या जरूरत थी। अगर उनकी जुबान फिसली है तो फिर आलाकामन ने उस पर क्या कार्रवाई की।

महाराष्ट्र ने गुरुवर्णनी देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री एकनाया दिए के बीच दिया तकरार बढ़ने के आसार दिया रहे हैं। दिए सरकार के दौरान स्थानीय विभाग के 3,200 करोड़ रुपये के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया है। तानाजी सावंत एवं विना किसी कार्य अनुभव के कंपनी को लैकेनिकल सफाई का टेका देने का आशोप लगा है। गुरुवर्णनी देवेंद्र फडणवीस ने दिए सरकार के दौरान की कथित अनियमिताओं के खिलाफ कार्यवाई शुरू कर दी है, दिए सरकार के कई फैसले स्थगित कर दिए गए, वही कुछ जो रह रही कर दिया गया। तानाजी सावंत दिए सरकार के दौरान स्थानीय मंत्री थे। उनके कार्यकाल के

शिवसेना-बीजेपी में बढ़ेगी तकरार!

दौरान अधिकारियों के तबालों और एम्बुलेंस खट्टी सहित हजारों करोड़ रुपये के खोटाले होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय विभाग के अधीन सभी



ठेका दिया गया। सीएम फडणवीस ने नियों के

आरोपी के साथ है सरकार : सप्काल



महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सप्काल ने बयान पर कड़ा विरोध जताया है। हर्षवर्धन सप्काल ने कहा है कि जब कोई पीड़िता खायाब समय से गुजरता है तो उसकी प्रतिक्रिया यहा होनी चाहिए, इसकी परिकल्पना करना भी समझ से पैदे है। वह यहां मंत्री का जिस तरह का बयान है, ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से ही संन्यास ले लेना चाहिए। वह यहा बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वह पीड़िता के साथ है या फिर आरोपी के साथ? मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार दो वर्षों, दो धमानों में लड़ाई लड़वाना चाहती है। जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह सरकार की विफलता को दर्शती हैं।

नेताओं से लेकर कानूनविदों ने की आलोचना

पुणे घटना को लेकर नेताओं से लेकर पूर्व न्यायाली तक ने आलोचना की है। पूर्व सीजेर्स डीवाई चंद्रपूर्ण ने कहा कि नियोंया घटना के बाद कानूनों में बहुत सारे बदलाव किए गए, हालांकि, हम केवल कानून बनाकर ऐसी घटना को नहीं रोक सकते। चंद्रपूर्ण ने कहा कि समाज पर बड़ी जिम्मेदारी है और इसके अलावा कानूनों का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बने कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। नियोंया जहां भी जाए उन्हें सुनिश्चित गहसूस करना चाहिए। वहीं संजय राजत ने कहा कि अगर राज्य में विषयी गतविधान मध्य विकास आयडी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला नेता अब तक राज्य गुरुद्वारा नंगालय के बाहर हंगामा कर रही होती। राजत ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की भाजपा नीति सरकार की लाइक्स बहिन योजना का नियंत्रण करते हुए पूछा, हर गहीने 1,500 रुपये देकर क्या आपने महिलाओं का आलासमान खीटी लिया है?

ओपेंडी और निजी संघिक के मानले में भी सक्त छाया आया है। नियोंया के ओपेंडी और सिंह की नियुक्ति के लिए 125 नाम लेने गए थे, जिसमें सींगा ने 109 नामों को नज़रीटी दी है। जबकि 16 नामों को रोक दिया है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह किसी लालाल को यह नियोंया नहीं देगे। इन नामों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके सुझाव को एकान्यका दिये गए थे। इस फैसले को उद्घाटन कर गृह ने भी तारीफी की थी। शिवसेना यूटीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य के शासन में अनुशासन लाने के लिए मज़बूत कदम उठ रहे हैं। सीएम फडणवीस ने भट्टाचार्य के नामे की सफाई शुरू कर दी है।

